राज्यपाल सचिवालय
राजभवन जयपुर

स्वतन्त्रता दिवस पर राज्यपाल की शुभकामनाएं

जयपुर 14 अगस्त। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने स्वतन्त्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र का स्वतन्त्रता दिवस पर संदेश अविकल रूप से प्रस्तुत है-

भाइयो और बहिनो,

-आज हमारा देश हर्षोल्लास के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

-मैं सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश की आजादी के संघर्ष में अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों के स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगलकामना करता हूं।

-मैं देश के उन सभी जांबाज सैन्यकर्मियों तथा पुलिसकर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

-देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात सभी जवानों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जिनकी वजह से हम सब आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं।

-आजादी के बाद देश के महान नेताओं ने विकास का लम्बा सफर तय करते हुए लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है जिससे भारत का मस्तक दुनिया के देशों के सामने हमेशा ऊंचा रहा है।

-आज इस पावन अवसर पर हमें यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप मन, वचन और कर्म से आचरण करने पर ही स्वाधीनता की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

-राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन देने के संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर है किन्तु कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के कारण अचानक स्थितियां विकट हो गयी हैं।

-कोरोना महामारी का प्रदेश में पहला केस आने के साथ ही राज्य सरकार ने 'राजस्थान सतर्क है' के मूल मंत्र के साथ काम शुरू कर दिया। देश में सबसे पहले लॉक डाउन लागू करने के साथ ही मानव जीवन की रक्षा के लिए सरकार ने त्वरित फैसले लेकर बचाव के उपाय शुरू कर दिए।

-कोरोना महामारी के प्रकोप की गंभीरता को समझते हुए सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञ चिकित्सकों, धर्मगुरुओं, भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उद्यमियों, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन, राज्य कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों एवं आमजन के सुझावों का सम्मान करते हुए प्रभावी प्रबंधन किया।

-प्रदेश में पहले कोरोना वायरस की जांच की कोई सुविधा नहीं होने के कारण जांच के लिए सैम्पल राज्य से बाहर भेजने पड़ते थे। आज राज्य में 45 हजार से अधिक जांचें प्रतिदिन की जा रही है।

-राज्य में अधिकतम जांचों से हमने संक्रमित क्षेत्रों को तुरंत चिन्हित करने के साथ-साथ रूथलैस कंटेनमेंट किया। इससे अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की रिकवरी रेट अधिक और मृत्यु दर कम रही है।

-'प्रदेश में कोरोना से किसी की मृत्यु न हो' यह सुनिश्चित करने के लिए प्लाज्मा थैरेपी प्रारंभ की गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर एवं कोटा मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की गई। अब हर जिले में इसका विस्तार किया जाएगा।

-प्रदेश में 130 डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, 286 कोविड केयर सेंटर, 1 हजार 593 संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में 90 हजार बेड्स, 43 हजार आइसोलेशन बेड्स, 890 वेंटीलेटर्स, 1 हजार 700 आईसीयू एवं पीपीई किट्स एवं दवाओं और उपकरणों की व्यवस्था भी की गई।

-कोरोना के उपचार के लिए गरीब से गरीब गंभीर रोगी को लगभग 40 हजार रुपये के जीवन रक्षक टोसिलीजूमेब व रेमडीसीविर इंजेक्शन मुफ्त उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

-लॉक डाउन के दौरान 'कोई भूखा न सोये' के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने गरीब एवं बेसहारा लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पैकेज एवं अन्य राहत उपायों की व्यवस्था कीए जिस पर लगभग 6 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए।

-प्रदेश के विषम आर्थिक हालात के बावजूद लगभग साढे 4 करोड़ लोगों को मुफ्त सूखा राशन किट और भोजन के पैकेट वितरित किए गए। इसके अलावा 79 लाख लोगों को 5 माह से निरंतर सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी दी जा रही है। साथ ही 35 लाख जरूरतमंद लोगों को 3 हजार 500 रुपये प्रति व्यक्ति नकद आर्थिक सहायता भी दी गई।

-सरकार द्वारा कोरोना वारियर्स की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

-कोरोना महामारी के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए 21 जून से 7 जुलाई, 2020 तक प्रदेशव्यापी विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया गया। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जागरूकता प्रदर्शनी एवं विभिन्न माध्यमों से जन जागरण गतिविधियां भी सतत रूप से जारी हैं।

-कोरोना से मुकाबला करने में कुशल प्रबंधन के कारण राजस्थान सरकार की सर्वत्र सराहना हुई। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने भी राज्य सरकार के कोरोना प्रबन्धन की प्रशंसा की।

-राज्य में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से भी कोरोना की रोकथाम के लिए वर्ष 2020-.21 एवं 2021-22 की निर्धारित राशि में से प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये की राशि केवल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने में खर्च की जाएगी।

-कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में चिकित्सकों के 2 हजार अतिरिक्त पद सृजित कर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।

-हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें अनिवार्य रूप से सतर्क रहना है। खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखते हुए हम अपने आपको और समाज को बचा सकते हैं।

-सरकार के सामूहिक प्रयासों का ही नतीजा रहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस को तेज गति से बढ़ने से रोकने में हम काफी हद तक सफल रहे हैं। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार आम आदमी के साथ खड़ी है और उनके जीवन की रक्षा के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

-आमजन में अत्यंत लोकप्रिय रही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में अब तक करीब 79 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की 712 दवाएं मुफ्त दी जा रही है। सरकार ने निःशुल्क दवाओं को दायरा बढ़ाते हुए इसमें जीवन रक्षक दवाओं को भी शामिल किया है।

-मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अन्तर्गत अब तक करीब 30 करोड़ 45 लाख निःशुल्क जांचें कर 15 करोड़ 59 लाख मरीजों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें 90 प्रकार की जांचों को शामिल किया गया है।

-आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में 1 सितम्बर 2019 से अब तक 8 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं जिनके इलाज पर 752 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

-शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इस वर्ष 167 ब्लाक मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्थापित कर इन्हें 'सेन्टर ऑफ़ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित किया जा रहा है।

-उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में इसी शैक्षणिक सत्र से 37 नये महाविद्यालय खोले गए हैं। राज्य के 10 स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में क्रमोन्नत भी किया गया है।

-बच्चों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार का दिन 'नो बैग डे' घोषित किया गया ताकि बच्चों को गैर शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय किया जा सके।

-निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में पहले 1 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले अभिभावक अपने ही बच्चों को प्रवेश दिला सकते थे। अब सरकार ने इस आय सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया है।

-युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 61 हजार 622 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी हैं।

-करीब 16 हजार 180 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए जा चुके हैं जिनकी प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र ही नौकरी प्रदान की जाएगी। इनके अतिरिक्त करीब 40 हजार विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है।

-मोस्ट बैकवर्ड क्लास यथा गुर्जर, गाडिया लुहार, बंजारा, रेबारी, रायका आदि वर्ग के लिए राजस्थान न्यायिक सेवाओं में आरक्षण 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

-संविधान की भावना के अनुरूप अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का कोटा पूरा करने के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से गंभीर है। सरकारी विभागों में एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षित बैकलॉग पदों को भरा जा रहा है।

-वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1 लाख युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1 लाख 46 हजार से अधिक शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर लाभान्वित किया गया है।

-रोजगार अवसर सुगम बनाने के लिए प्रारंभ किये गये ऑनलाइन राज-कौशल लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल पर 52 लाख श्रमिकों एवं 11 लाख नियोजकों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 30 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई है।

-असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए 'स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स ' का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

-राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों को उनकी उपज का ई-नीलामी के माध्यम से अधिकतम मूल्य दिलाने के लिए सभी 144 मंडियों में ई-नाम प्रोजेक्ट लागू किया गया है।

-प्रदेश में 400 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले गये हैं । पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में 2 करोड़ 94 लाख पशुओं की चिकित्सा कर 1 करोड़ 8 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है।

-राज्य सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं के लिए इसी वित्तीय वर्ष में 285 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है।

-प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को वर्ष 2020-21 में 10 हजार करोड़ रुपये का खरीफ में और 6 हजार करोड़ रुपये का रबी में ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जायेगा।

-इस वर्ष किसानों को पहले के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक फसली ऋण दिया जा रहा है। राज्य में 6 जुलाई तक 22 लाख 64 हजार किसानों को 7 हजार 26 करोड़ रुपये का फसली ऋण दिया चुका है।

-किसानों को लॉक डाउन के दौरान राहत देने के लिए अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण 2019-20 को चुकाने की अवधि 31 मार्च से 31 अगस्त, 2020 तक बढ़ाई गई। इससे 22 लाख किसानों को मुफ्त ब्याज सुविधा का लाभ मिला है।

-सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि ऋण पर किसानों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून, 2020 की गई।

-ओलावृष्टि से 15 जिलों के 861 गांव तथा टिड्डी दल से प्रभावित 8 जिलों के 960 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। प्राकृतिक आपदा से फसलों में खराबा होने पर प्रभावित पात्र कृषकों को सहायता वितरण करने हेतु इस वर्ष में 223 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

-लॉक डाउन के बावजूद वर्ष 2020.21 में समर्थन मूल्यों पर गत वर्ष से डेढ़ गुना अधिक 22 लाख 19 हजार मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई जिससे 2 लाख 19 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह 3 लाख 46 हजार मैट्रिक टन सरसों एवं 6 लाख 15 हजार मैट्रिक टन चने की समर्थन मूल्यों पर खरीद की गई जिससे 3 लाख 77 हजार किसानों को लाभान्वित किया गया है।

-वित्तीय वर्ष 2019.2020 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 2 हजार 180 करोड़ रूपये व्यय कर 10 हजार 850 हैक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवायी गयी। वर्ष 2020-2021 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 3 हजार 193 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान रखा गया है।

-भारत सरकार के केंद्रीय बोर्ड ऑफ़ इरीगेशन एण्ड पावर द्वारा वर्ष 2020 में राज्य को जल दक्षता सुधार कार्यक्रमों के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नर्मदा परियोजना तथा इंदिरा गांधी नहरी तंत्र में किए गये कार्यों के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

-ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की 37 हजार 247 करोड़ रुपये की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट से राज्य के 13 जिलों में पेयजल तथा 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता हो सकेगी।

-राज्य की 7 हजार 355 करोड़ रुपये की लागत वाली महत्वाकांक्षी परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना से बारांए झालावाड़ और कोटा जिलों के 1 हजार 821 गांवों में पेयजल पहुंचेगा और 2 लाख 80 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा।

-राज्य सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इन दोनों परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने और इनकी जल्द क्रियान्विति का आग्रह किया गया है।

-प्रदेश में वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जलस्रोत से 13 शहरों, 2 हजार 52 गांवों एवं 2 हजार 152 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2020.21 हेतु 7 हजार 662 करोड़ रुपये की कार्ययोजना अनुमोदित की जा चुकी है।

-ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 201-.20 में लगभग 1 हजार 47 करोड़ रुपये व्यय कर 19 हजार 658 विकास कार्य पूर्ण कराये गये हैं।

-गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजीविका योजना में लगभग 1 लाख 76 हजार स्वयं सहायता समूहों को रोजगार देने हेतु 1 हजार 658 करोड़ रुपये का संबल प्रदान किया गयाए जिससे 20 लाख 54 हजार परिवार लाभान्वित हुए हैं।

-प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की दृष्टि से प्रदेश में 57 नयी पंचायत समितियों एवं 1 हजार 456 नयी ग्राम पंचायतों के साथ नए उपखंड, तहसील, उपतहसीलों एवं नए राजस्व ग्रामों का गठन किया गया है।

-समग्र ग्रामीण विकास की दृष्टि से 183 ग्राम पंचायतों में 144 करोड़ रुपये की लागत से विकास पथ बनाये जा रहे हैं।

-प्रदेश में 8 हजार 956 करोड़ रुपये की लागत से 3 हजार 692 किलोमीटर नई सड़केंए 414 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों, 2 हजार 688 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गों व 16 हजार 111 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

-महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के पहले चार माह में ही 60 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाकर 21 करोड़ 59 लाख मानव दिवस सृजित किये जा चुके हैं।

-राज्य सरकार ने इस बार भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पांच साल तक कृषि विद्युत दरों में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का भार वहन किया जा रहा है।

-वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मार्च 2020 तक प्रदेश के विद्युत वितरण व प्रसारण तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 370 ग्रिड सब-स्टेशन स्थापित कर 1 लाख 39 हजार कृषि कनेक्शन एवं 9 लाख 75 हजार घरेलू कनेक्शन जारी किये गये हैं।

-औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने 'वन स्टॉप शॉप ' प्रणाली शुरू की है। एकल खिड़की व्यवस्था के तहत दिसम्बर 2018 से अब तक 18 हजार 165 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के 15 हजार 460 प्रस्तावों के लिए अनुमति जारी की गयी है।

-वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2 लाख 13 हजार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) फाइल किये हैं। इन उद्यमों में 26 हजार 315 करोड़ रूपये का निवेश और 9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ हुआ है।

महिलाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने महिला दिवस और रक्षा बन्धन पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है जिसका 21 लाख महिलाओं ने लाभ उठाया।

-अल्पसंख्यकों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वर्ष अब तक 27 हजार 933 अभ्यर्थियों के बैंक खातों में 20 करोड़ 73 लाख रुपये तथा मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना में 3 हजार 188 अभ्यर्थियों के बैंक खातों में 8 करोड़ 21 लाख रुपये की राशि जमा कराई गई है।

-वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 4 हजार 558 यात्रियों को रेल एवं 3 हजार 589 यात्रियों को हवाई जहाज से मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई गई। इनमें से पहली बार 2 हजार 113 यात्रियों को नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की मुफ्त यात्रा करवाई गई है।

-प्रदेश में पहली बार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने और खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पदक विजेताओं को सीधी सरकारी नौकरियां दी जा रही है। सरकार ने ओलम्पिक खेलोंए एशियन गेम्स एवं कोमन वेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की इनामी राशि में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है।

-प्रदेश में भाईचारे का वातावरण, शांति, समृद्धि एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र के साथ कानून एवं शांति व्यवस्था को माकूल बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।

-संगठित अपराधोंए माफियाओं, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति व जनजाति सहित कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम पर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

-भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के संबंध में राज्य सरकार शुरू से ही जीरो टोलरेंस की नीति पर चल रही है। राज्य सरकार कृत संकल्प है कि भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

-आम लोगों का पुलिस के साथ सहज संपर्क बनाने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 127 थानों में स्वागत कक्ष बनाए जा चुके हैं।

-राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की 150वीं जयन्ती वर्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी के 75वें जन्म दिवस समारोह की अवधि को एक वर्ष के लिए और बढ़ाया गया है।

-राज्य सरकार बाबा साहेब डाॅ. भीमराव अम्बेडकर की मूल भावना के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करनेए देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाये रखने और समस्त वर्गों, समाजों और समुदायों को साथ लेकर विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है।

-मैं प्रदेशवासियों का आह्वान करता हूं कि वे कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी सभी सरकारी दिशा-निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए सावचेत करें।

-मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर प्रदेश में कोरोना महामारी ‘कोविड-19’ पर प्रभावी अंकुश लगाने में कामयाब होंगे।

-आइए ! आप और हम सब आजादी के इस पुनीत पर्व पर संवैधानिक दायित्वों एवं राष्ट्रीय कत्र्तव्यों के प्रति और अधिक जिम्मेदार होने की शपथ लें। राजस्थान को समृद्धए विकसित और खुशहाल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

जयहिन्द!

——

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
राज्यपाल, राजस्थान
9829271189